

समावेशी विकास से समृद्धि की राह पर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश ने समावेशी विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए, गाँवों की तस्वीर बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की हैं जिन्हें देश भर में सराहा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए की जा रही कोशिशों के तहत मनरेगा कन्वर्जेंस से मध्यप्रदेश में मेरा खेत मेरी माटी उपयोजना शुरू की गयी है। देश भर में अपनी तरह की इस अनूठी योजना के जरिए प्रदेश के 52 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत कृषकों को जिनके पास दो एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है उनकी कृषि योग्य तथा गैर कृषि योग्य भूमि पर रोजगारमूलक कार्य होंगे।

मनरेगा कन्वर्जेंस से ही ग्रामों में संपर्क सुविधा के विकास के लिए सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना भी शुरू की गयी है। इस उपयोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में मजरे टोलों और खेत समूहों को जोड़ने के लिए बारहमासी ग्रेवल सड़कों का निर्माण होगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में शुरू हुई पंच-परमेश्वर योजना में अब तक 7844 किलोमीटर लम्बे सीमेंट कांक्रीट युक्त आंतरिक मार्ग बन चुके

हैं। मनरेगा कन्वर्जेंस के जरिए संचालित इस अनूठी योजना में ग्राम पंचायत को आबादी के मान से पाँच से पंद्रह लाख तक की राशि हर साल आवंटित की जा रही है। इस योजना में अब तक सभी 23006 ग्राम पंचायतों को तीन हजार पाँच सौ दो करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों में पक्के आंगनवाड़ी भवन नहीं हैं या जो आंगनवाड़ी किराये के भवनों में संचालित है वहाँ अब नये आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कन्वर्जेंस से किया जायेगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में मनरेगा राशि के साथ-साथ बी.आर.जी.एफ. एकीकृत विकास कार्यक्रम (आई.ए.पी.) तथा महिला बाल विकास मद की राशि को भी शामिल किया जा सकेगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन की लागत 5.83 लाख रुपये होगी। इन भवनों की सुरक्षा के लिये बाउंड्रीवाल और पेयजल के इंतजाम के लिए हैण्डपम्प की लागत 1.97 लाख रुपये अतिरिक्त होगी।

प्रदेश में गरीब तथा कमजोर तबकों के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के लिए भी राशि अब प्रति विवाह 25 हजार रुपये कर दी गयी है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल को सराहा



संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल को सराहा

सुदूर ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं मुहैया करवाने तथा अल्ट्रा स्माल बैंकों (यूएसबी) के जरिए हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने के मध्यप्रदेश के वित्तीय समावेशन मॉडल समृद्धि की व्यापक सराहना हुई। मध्यप्रदेश के इस अनूठे नवाचार की सफलता के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को भोपाल में जारी किया गया। इस अवसर पर सचिव वित्त विभाग भारत सरकार श्री सुमित बोस, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश श्री

अंटोनी डिसा और संयुक्त राष्ट्र की नई दिल्ली स्थित रेसिडेंट को-ऑर्डिनेटर और यूएनडीपी की रेसिडेंट रिप्रजेंटेटिव सुश्री लिज ग्रेन उपस्थित थीं। इस अवसर पर श्री सुमित बोस ने कहा कि मध्यप्रदेश मॉडल समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने इस अवसर पर कहा कि सामाजिक समावेशन के लिए आर्थिक समावेशन जरूरी है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित 14 हजार 667 गांवों के लिए करीब 3 हजार अल्ट्रा स्मॉल बैंकों की स्थापना की जा रही है। डेढ़ वर्ष में अब तक 2071 अल्ट्रा स्मॉल बैंक सुदूर गांवों में खुल चुके हैं। पहले सुदूर गांवों में बैंकिंग सुविधाओं के लिए लोगों को 20 से 90 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता था।

इन अल्ट्रा स्मॉल बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण सफलता से हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में बीपीएल परिवारों, वृद्धजन, निराश्रित, निःशक्तजन और विधवाओं को भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता तथा पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में जमा हो रही है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि अल्ट्रा स्मॉल बैंकों के जरिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लेन-देन अब तक हो चुका है।



बेटी बचाओ अभियान

बेटी बचाओ अभियान

बेटी बचाओ अभियान का उद्देश्य है कि हर परिवार में लड़कियों का जन्म हो सके। यह अभियान लड़कियों के जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है।

संघीय सरकार द्वारा 2006 में शुरू किया गया यह अभियान लड़कियों के जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है।

इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों के जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है।

संघीय सरकार द्वारा 2006 में शुरू किया गया यह अभियान लड़कियों के जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है।



बेटी बचाओ अभियान

नारी शक्ति की प्रगति और कल्याण के लिए



मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को भोपाल में स्वागतम् लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत जीवन भर नारी के स्वागत और सम्मान के अवसर निर्मित किये जाएंगे। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं ने सृष्टि की सुरक्षा का दायित्व निभाया है। लाइली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाओं ने समाज की मानसिकता बदली है।

योजना का उद्देश्य - समाज में बच्चियों को जन्म के पूर्व एवं जन्म के पश्चात समान रूप से स्वीकार करना। बालिकाओं के जन्म से संबंधित भ्रूतियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करना। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सकारात्मक सोच तथा समानता हेतु वातावरण का निर्माण करना।

योजना में : जिले के सोनोग्राफी सेन्टर संचालित करने वाले चिकित्सकों, न्यायाधीश, वकील, स्वैच्छिक संगठनों, धर्मगुरुओं की सहभागिता से गर्भाधान से पहले और जन्म से पहले निदान तकनीक अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। चिकित्सालयों में बेटियों के जन्म पर जच्चा-बच्चा का स्वागत, ग्राम एवं वार्ड में जन्म लेने वाली बेटियों का स्वागत तथा उनकी माताओं का सम्मान करना। समस्त शालाओं में स्वागत लक्ष्मी कार्यक्रम आयोजित करते हुए महिला शिक्षिकाओं तथा छात्राओं का सम्मान। ग्राम पंचायतों की बैठकों का प्रारंभ महिला सरपंच, पंच के स्वागत से किया जायेगा। ग्राम सभा का प्रारंभ ग्राम की सबसे वृद्ध महिला, उसी माह जन्मी बालिका तथा ग्राम की मेधावी बालिका के स्वागत के साथ किया जायेगा।

